They must be in service on and after 1-1-1964 to be entitled to the pension.

Shri Indrajit Gupta: Retired.

श्री काशीराम गुप्त : [क्या] सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जो पेन्शन रुपये की शक्ल में दी जाती है, उस का एक बड़ा भाग गांवों में जमीन की शक्ल में दिया जाये, ताकि वे लोग खेती पर अपना जीवननिर्वाह कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सजेस्टियन फ़ार एक्शन है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको ज़मीन दी जाये ।

श्री काशीराम गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात पर भी विचार हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : विचार बहुत दफ़ा हुआ है ।

श्री यशपाल सिंह : जो लोग धर्म-युद्ध में लड़ते-लड़ते मारे गये, जो लोग इस वक्त सर्विस में हैं और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, इन तीनों कैटगरीज़ के लिए अलग अलग कितना रुपया सरकार ने मंजूर किया है ?

Dr. D. S. Raju: I can give it, but I want notice for this.

Shri S. M. Banerjee: From the statement it appears, as put by my hon. friend Shri Indrajit Gupta, that this pensionary benefit is admissible to widows and children of those who were in service on 1-1-1964. I want to know what is going to happen to the families of those jawans who were killed during the Chinese aggression. It clearly means that this scheme will not apply to those who died in October, November and December, 1962.

Dr. D. S. Raju: Those who die in actual field service conditions have got their own pension benefits.

Dr. Sarojini Mahishi: May I know the position of jawans in the Territorial Army with reference to the application of this family pension scheme?

Dr. D. S. Raju: It applies to all the temporary commissioned officers, E.C.Os and short service commissioned officers provided they are married. order to boost up their pension benemotion is always there.

Shri M. R. Krishna: May I know, as the officers of the Defence forces are given time-scale promotions in order to boost up their pension benefits, etc., whether the same thing is done for jawans and JCOs?

Dr. D. S. Raju: The time-scale promotion is always there.

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि चाइना के हमले के समय जो लोग मारे गये, क्या उनकी फैमिलीज़ को कुछ दिया गया है ; यदि हां, तो क्या दिया गया है ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): For those who die in the fields, in actual field service conditions, there are special benefits. This scheme applies to those persons who die in the normal course while in service. We have made payments to the families of those persons who have died in the fields.

National Defence Fund

\+

*428. **Shri Rameshwar Tantia:**
Shri Bishanchander Seth:
Shri Dhaon:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri B. P. Yadava:
Shri Bagri:
Shri J. P. Jyotishi:
Shri Himatsingka:
Shri E. Madhusudan Rao:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the total amount collected so far under the National Defence Fund; and

(b) how much of it has been spent so far?

The Parliamentary Secretary to the Prime Minister (Shri Lalit Sen): (a) The total amount brought into the Central Account of the National Defence Fund upto the 19th September, 1964 was Rs. 57.98 crores.

(b) A total expenditure of about Rs. 33 crores has so far been authorised.

Shri Rameshwar Tantia: May I know whether it is a fact that some misappropriation of the National Defence Fund has been done by some persons and, if so, whether the Government has enquired into that, and may I also know what was the amount involved and what steps they are taking?

Shri Lalit Sen: Various complaints regarding misappropriation have been received by the Prime Minister from time to time. As the responsibility for collection of these funds rests solely with the States, all such complaints are referred to them for necessary action.

Shri Rameshwar Tantia: May I know whether the Government will continue the National Defence Fund scheme?

Shri Lalit Sen: Yes, Sir.

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा कोष का धन अधिकतर किन किन कामों पर ख़र्च किया जाता है ।

श्री ललित सेन : श्रीमन्, अभी तक जो ख़र्च का ब्यौरा है , ...

अध्यक्ष महोदय : यह बतला दीजिए कि वह रुपया अधिकतर किन किन कामों पर ख़र्च किया जाता है ।

श्री ललित सेन : इस वक्त तक 27 करोड़ रुपये की रकम डिफेंस एक्विपमेंट ख़रीदने पर ख़र्च की गई है और प्राविज़न आफ़ एमिनिटीज़ फ़ार दि ट्रूप्स एंड दि वैलफेयर आफ़ देयर फ़मिलीज़ पर 35 लाख रुपया ख़र्च हुआ है ।

श्री बागड़ी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रक्षा कोष अमली तौर से बन्द कर रखा है, जो कि इस बात से ज़ाहिर है कि इस सदन के कुल 11 मेम्बर रक्षा कोष में रुपया देते हैं और बाकी ने देना बन्द कर दिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यों वह फ़ंड कोई बिल्कुल ख़त्म कर देने की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों की साधारणतः यह राय रही है कि जो लोग खुद-ब-खुद रुपया भेजना चाहें, वे तो भजें, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई ड्राइव न चले और जैसे रुपया एकत्र करने के लिए हम लोग पहले तेज़ी से काम किया करते थे, वह न हो । हमने चीफ़ मिनिस्टरों को यह कहा भी था । अगर कोई अपनी तरफ से भेजना चाहे, तो भेज सकता है ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी: मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की जितनी शिकायतें केन्द्रीय शासन के पास आईं और क्या केन्द्रीय शासन ने स्टेट्स को यह हिदायत दी कि भ्रष्ट व्यक्तियों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कदम उठाए जायें ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं संख्या तो नहीं बता सकता कि कितनी शिकायतें आईं, लेकिन हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी मजबूती से लिखा है कि इन चीजों की जांच-पड़ताल और ज़रूरी कार्यवाही की जाये ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: May I know whether under the Centrally sponsored scheme, the whole amount which has already been collected by the State Governments has been audited so far, and if so, whether any shortfall has been noticed?

Shri Lalit Sen: In December, 1963, a circular was sent to all the States asking them to withdraw the old receipt-books and have an audit conducted with regard to all the collections made by them. As far as we know, they are taking necessary action in this matter.

श्री हुकम चन्द कछवाय : एक प्रश्न अभी के उत्तर में बताया गया है कि ग़बन की कुछ शिकायतें प्रधान मंत्री को मिली हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने रुपये के ग़बन की शिकायतें प्रधान मंत्री के पास आई हैं और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की ओर से उस कोष में कितना रुपया दिया गया है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जो दो, चार, दस, बीस शिकायतें आई हैं, उस से हम अन्दाजा करें कि कितना ग़बन आ है या उस से ग़बन का अन्दाजा करें, यह बात नहीं है । लेकिन इस में सीधी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है । उन्होंने ही रिसीदों की किताबें छपवाई थीं और उन्होंने ही बांटी थी । पहले ही उन को यह बात साफ़ कर दी गई थी कि रुपया इकट्ठा करने की, और अगर उस में कोई गलती हो, तो उस की, पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को उठानी पड़ेगी । इसलिए यह बात उन पर छोड़ी गई है । जैसा कि श्री ललित सेन ने कहा है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : विदेशों में रहने वाले भारतीयों से कितना रुपया आया है ?

श्री ललित सेन : वे आंकड़े इस समय नहीं हैं ।

Shri Himmatsinhji: May I know the total amount of gold collected for the National Defence Fund?

Shri Lalit Sen: The total amount with the N.D.F. is 2340237.483-1|2 grms.

Shri Solanki: How much of this gold has been utilised for purchase of weapons and armaments?

Shri Lalit Sen: As I have already stated, a total amount of Rs. 27 crores has been authorised for buying defence equipment.

श्री राम सहाय पाण्डेय : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि चीनी आक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए जब साधन-प्रसाधनों की अधिक आवश्यकता है, जब कि धन की बड़ी आवश्यकता है, तो धन एकत्रित करने की मशीनरी में शिथिलता आने का क्या कारण है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहस करने लगे हैं । यह गवर्नमेंट की पालिसी है ।

Shri A. N. Vidyalankar: May I know whether any rules have been made for the disbursement of these funds?

Shri Lal Bahadur Shastri: Yes, there are rules governing the disbursement.

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री को पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने जिस सोने से तोला था, उस में कुछ पीतल निकला था ?

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री कपूर सिंह : इस प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि हर एक आदमी जोहरी तो नहीं हो सकता है ।

श्री रामेश्वरानन्द : जवाब मिलना चाहिए । यह सरकार तो जोहरियों की जोहरी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन को कहूंगा कि वह माननीय सदस्य को सोना दिखावें ।

Shri Indrajit Gupta: The hon. Prime Minister said a little while ago that the Central Government had issued directives to the effect that no positive drive should be continued. What is the present attitude of Government in those cases where indirect donations to the Defence Fund were organised by people who agreed to work on Sundays or extra hours, extra shifts and so on? In their case, would this be there voluntarily or could they revert to their former working system where they wanted it?

Shri Lal Bahadur Shastri: If it was voluntary, then it is open to them, if they want to continue, to do so. It would be most welcome. If they do not want to continue, I do not think Government will in any way compel them.

Migrants from Indian Enclaves in East Pakistan

\+

*429. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Indrajit Gupta:
Shri Bade:
Shri Vidya Charan Shukla:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 917 on the 6th April, 1964 and state:

(a) whether people residing in Indian Enclaves in East Pakistan are still migrating to West Bengal due to insecurity of the life and property there; and

(b) what was the response of the East Pakistan Government to the firm protest that was lodged with them at the State level?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) Yes, Sir. 1886 persons have come over to West Bengal from Indian Enclaves in East Pakistan between 22nd March and 31st August, 1964. However, the situation in the Enclaves is now reported to be peaceful.

(b) The East Pakistan Government has denied allegations of harassment caused by Pakistan nationals to the residents of Indian Enclaves.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह बता सकती है कि अब रोजाना कितने लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आ रहे हैं ?

Shrimati Lakshmi Menon: I have not got the figure, but now the situation is normal and there is no further migration from the enclaves.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को पता है कि जो आने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिफिकेशन कार्ड हासिल करने में, वीसा और परमिट इत्यादि हासिल करने में बहुत दिक्कत होती है और दफ्तरों के ऊपर उनको बहुत ज्यादा खड़े रहना पड़ता है, यदि हां, तो उसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है ?

Shrimati Lakshmi Menon: They are given the same relief and rehabilitation benefits as other refugees from East Pakistan, although they are not refugees.

Shri Indrajit Gupta: Since these are Indian enclaves, Indian territory, what is there to prevent, if necessary, our despatching troops or security forces and posting them in those areas to see that the inhabitants are not harassed in any way?

Shrimati Lakshmi Menon: The hon. Member would recall there is an agreement regarding exchange of Indian enclaves in Pakistan with Pakistan enclaves in India. The proposal is under consideration. Necessary legislation has been passed. We are only waiting for demarcation so that the date can be fixed.

Shri Indrajit Gupta: My question was not about exchange of enclaves but about protection of the inhabitants in Indian territory who are being subjected to repression or harassment.